

jftLV^{ah} laö Mhö ,yö&33004@99
33004/99

REGD. NO. D. L.-

la- 26]

ubZ fnYyh] c'gLifrokj] tuo]h 14] 2016@ikS''k 24] 1937

No. 26]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 14, 2016/ PAUSA 24, 1937

कारपोरेट कायभाग

मंालय

अधिसूचना

नई ढदली, 13 जनवरी,

2016

सा.का.नि. 26(अ).—कश्तीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) कऱ धारा 469 के साथ पढठत धारा 125 कऱ उपधारा (5), उपधारा (6) और उपधारा (7) ढरारा ँदङ् शिषय का ँयोग करते शए िनिलिखत िनयम बनाती है, अथाभात् –

1. संिीत नाम, ाि और ँरंभ.- (1) इन िनयम का संिीत नाम िविनधानकताभा िशिी और संरिण िनिध

ंाधिकरण (अण्यी और सदंय कऱ िनयुि, बैठक का आयोजन और कायाभागलय और अधिकाइरय के िलए उपाबंध) िनयम, 2016 है ।

2. ये िनयम राजपू मश ँकाशन कऱ तारीख को ँवृह हगे।

2. पहरभाषाएं.- (1) इन िनयम मश, जब तक संदभभा से अउयथा अपेिीत न हो, -

(क) “अधिनयम” से कंपनी अधिनियम, 2013 अभंेत है;

(ख) “ंाधिकरण” से अधिनयम कऱ धारा 125 कऱ उपधारा (5) के अधीन गढठत िविनधानकताभा

िशिी और संरिण

िनिध ंाधिकरण अभंेत है;

(ग) “अण्यी” से इन िनयम के िनयम (5) के अधीन िनयु ंाधिकरण का अण्यी अभंेत है;

(घ) “कंपनी” से अधिनयम कऱ धारा 2 कऱ उपधारा (20) मश यथापहरभाषित कंपनी अभंेत है और इसमश ब.ककारी

कंपनी (उपद्रम का अज्ञान और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) क॥ धारा 2 क॥ उपधारा

(घ) और

197 GI/2016 (1)

ब.ककारी कंपनी (उपद्रम का अज्ञान और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) क॥ धारा 2 के

खंड (ख) मंथ यथापहरभाषित 'त०थानीय नया ब.क' सि०मिलत है;

(ड) "निध" से अधिनियम क॥ धारा 125 के अधीन ०थापित विनिधानकताज्ञा शि०ा और संर०ण

निध (आईपीएफ) अभि०ेत है;

(च) "विनिधानकताज्ञा" से ऐसा ०ि० अभि०ेत है जि०सने अधिनियम के अधीन रिज०लीकृत ढकसी

कंपनी के ढकसी ँक०म या योजना के अधीन शेयर ० या ँडब०चर ०, बंधपू या ँनि०ेप मंथ पैसा लगाया है;

(छ) "सद०य" से अधिनियम क॥ धारा 125 क॥ उपधारा (6) के अधीन ँनयु ० ०ा०िधकरण के सद०य

अभि०ेत ह.; (ज) "धारा" से अधिनियम क॥ धारा अभि०ेत है।

(2) इन ँनियम ० मंथ ०यु ० शूद ० और अभि०ि०य ० जि०ह० पहरभाषित नह० ढकया गया है ँकतु

अधिनियम मंथ या कंपनी (पहरभाषा यूर ० का विनिद०श) ँनियम, 2014 मंथ पहरभाषित ढकया गया है, के

०मश: वही अथ० ह०गे जो अधिनियम या उ ० ँनियम मंथ ढदए गए ह.।

3. ०ा०िधकरण क॥०थापना.- ०ा०िधकरण क॥ ०थापना ऐसी तारीख को क॥ जाएगी जो क००ीय

सरकार अधिसूचित करे। 4. ०ा०िधकरण का संघटन.- (1) ०ा०िधकरण ँनिलिखत से ँमिलकर

बनेगा, अथा०ात् –

(क) अ०य०;

(ख) छह सद०य; और

(ग) मु०य काय०पालक अधिकारी ।

(2) मु०य काय०पालक अधिकारी ०ा०िधकरण का संयोजक होगा।

5. ०ा०िधकरण का अ०य०.- सिचव, कारपोरेट काय० मं०ालय ०ा०िधकरण के पदेन अ०य० ह०गे।

6. ०ा०िधकरण का मु०य काय०पालक अधिकारी.- क००ीय सरकार मु०य काय०पालक अधिकारी के पद पर ढकसी ०ि० क॥ ँनयुि० करेगी।

7. ँाधिकरण के सदंय.- कशंीय सरकार िनिलिखत को ँाधिकरण के सदंय को ढप मश िनयु कर सकेगी, अथाभात्-

(i) भारतीय ढरजवभा ब.क ँनारा पदेन सदंय के ढप मश नामिनंद ि िजसका दजाभा कायभापालक िनदेशक से कम न हो; (ii) भारतीय ँतिभूति और िविनमय बोडभा ँनारा पदेन सदंय के ढप मश नामिनंद ि िजसका दजाभा कायभापालक िनदेशक से कम न हो; (iii) चार ँतिस्ति ि, जो िवड, ँबंधन, लेखांकन या िविध मश िवशेष िान और अयूनतम पंंह वष का अनुभव रखते ह। इन ँे 0 मश से ँयेक िवषय से एक

ि िनयु ढकया जाएगा और ऐसे ि के पास ऐसा िवशेष िान या

वसायिक अनुभव होगा, जो कशंीय सरकार कऱ राय के अनुसार ँाधिकरण के िलए उपयोगी होगा।

8. ँाधिकरण के सदंय कऱ िनबंधन.- (1) िनयम 7 के खंड (iii) के अधीन िनयु ँाधिकरण के सदंय कऱ िनबंधन

तीन वषभा होगी और वह पुनः िनयुि का पा होगा;

परंतु कोई सदंय तीन िनबंधन से अधिक तक पदधारण नह कर सकेगा।

परंतु यह और ढक कोई सदंय उसकऱ िनबंधन के पू ात् तीन वषभा कऱ उपशमन अविध के पूात् ही पुनः िनयुि का पा होगा।

(2) उपिनयम (1) मश अंतः ढकसी बात के रहते ञए भी, कशंीय सरकार िनयम 7 के खंड (iii) के अधीन िनयु ढकसी सदंय कऱ सेवा उपिनयम (4) मश िलिखत कारण के िलए तीन महीने से अयून अविध कऱ िलिखत नोडटस देकर उपिनयम (1) के अधीन िविनंद अविध के सम्रा होने से पूवभा सम्रा कर सकती है और ढकसी सदंय के पास भी कशंीय सरकार को

1Hkkx IIµ[k.M 3(i)°

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

3

तीन महीने से अयून अविध कऱ िलिखत नोडटस देकर उपिनयम (1) के अधीन िविनंद अविध के समाि से पहले

पदयाग

करने का अधिकार होगा।

(3) नियम 7 के खंड (iii) के अधीन नियुक्त सदस्य का कार्यकाल तीन वर्ष का अवधि या 65 वर्ष का

आयु, जो भी पूर्वानुतर हो,

तक होगा।

(4) केन्द्रीय सरकार किसी सदस्य को कार्यालय से हटा सकती है, यदि वह—

(क) हटा लिया है या किसी समय हटा लिया याचिनणायन किया गया है;

(ख) विकृतित है और किसी समित् यायालय द्वारा यह याचिनणायन किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार का राय मः किसी अपराध का सिद्धोष है, जिसमः नैतिक अधमता भी अंतर्वलित है;

(घ) केन्द्रीय सरकार का राय मः अपने पद का इस तरह दुपयोग किया है कि उसका लगातार कार्यकाल लोकिहत के लिए हािनकारक होगा।

परंतु किसी सदस्य को इस उप-नियम के अधीन मामले का सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दए िबना नहए हटाया जाएगा।

9. ँाधिकरण के अधिकाइरय और कमकाइरय का संया.- ँाधिकरण मः अधिकाइरय और अय

कमकाइरय का संया इन

नियम का अनुसूची I मः अधिकित कः तरह होगी जिससे िलिपकः सहायता और दन-ितदन के कायका हो सकः।

10. ँाधिकरण के कायका.- (1) अधिनयम के उपबंध के अधीन, ँाधिकरण का कतका

िविनधानकता िशित और संरित

निध का ँशासन करना होगा।

(2) ँाधिकरण के मामल का साधारण ँबंधन मुक्त कायकापालक अधिकारी करंगे, जो ँाधिकरण

द्वारा उहः ँाधिकृत कः गई

सभी शिक्त का ँयोग कर सकते ह।

(3) मुक्त कायकापालक अधिकारी अयित कः अधित और िनदेशानुसार सभी कायका करंगे।

(4) उपाबंध क २ ापकता पर २ तिकूल २ भाव डाले िबना, २ ाधिकरण के काय म ३ िनिलिखत सिमिलत ढकए जाएंगे,

अथाभात्:-

(क) २ ाधिकरण, अपने काय के िनरीण के िलए ंथायी सिमितय का गठन कर सकेगी।

(ख) २ ंयेक सिमित म ३ दो सदंय म ३ समािव हंगे, मुय कायभापालक अधिकारी और संबंिधत कायाभांमक २ मुख, जो

सिमित के सिचव हंगे। सिमित क ३ अय्यता एक पदेन सदंय ंद्वारा क ३ जाएगी।

(ग) सिमित ढकसी िविनंद मुंे पर अपेित होने पर िविशान और दंता वाले िवशेषी को भी आमंित कर

सकती है;

(घ) अपेित होने पर २ ाधिकरण िनिध और शेयर २ बंधन से संबंिधत कायभा आउटसोसभा भी करवा सकती है।

(ङ) २ ाधिकरण के २ ापक कायाभांमक २ भाग इन िनयम क ३ अनुसूची-2 के अनुसार हंगे।

4

THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

[PART II—SEC.

3(i)] 11. अधिवेशन.- (1) २ ाधिकरण और इसक ३ सिमितयां ऐसे समय और ंथान पर बैठक करंगी जो यह आवंयक समझे। (2) २ ाधिकरण और इसक ३ सिमितयां बैठक के आयोजन के िलए अपनी ंवय क ३ २ ढया अवधाडरत करंगे।

(3) यडद २ ाधिकरण या इसक ३ सिमितय को मुयालय नई ढदली के अलावा बैठक का आयोजन अयु करना है तो २ ाधिकरण के

अय्यता से इसके कारण उपदशत करते णए अनुमोदन अभंा करना होगा।

(4) २ ाधिकरण और इसक ३ सिमितयां एक ितमाही म ३ कम से कम एक बैठक और एक िवड्रीय वषभा

म ३ ऐसी चार बैठक करंगी:

परंतु लगातार दो

बैठक म ३ एक सौ बीस ढदन से अधिक अंतराल नहल होना चाहिए।

(5) २ ाधिकरण क ३ बैठक क ३ अय्यता, अय्यता ंद्वारा क ३ जाएगी।

(6) यडद ढकसी कारण के िलए अय्यता बैठक म ३ उपिंथत होने म ३ असमथभा ह. तो सदंय ंद्वारा

बैठक मऽ उपिंथत सदंय□ मऽ से चुना गया कोई अऽय सदंय बैठक कऽ अण्यैता करेगा।

(7) ँऽाधिकरण या इसकऽ ढकसी सिमित मऽ ढकसी ँऽपर मतभेद होने के मामले मऽ बऽमत को अंतिम िनणऽणय माना जाएगा।

(8) ँऽाधिकरण कऽ ढकसी बैठक मऽ कारबार के सं

वहार मऽ गणपूऽत ँऽाधिकरण के िनयु□ सदंय□ के 50% से अधिक होगी।

(9) ढकसी सिमित कऽ ढकसी बैठक मऽ कारबार के संवहार मऽ सिमित के दो सदंय गणपूऽत का गठन करऽगे।

(10) ँऽाधिकरण या सिमित के ढकसी गैर शासकऽय सदंय ँऽऽारा या िविशऽ आमंऽी ि□ ँऽऽारा

ँऽाधिकरण या सिमित के

कायऽण के संबंध मे कऽ गई याऽा□ के िलए बैठक मऽ उपिंथत होने के िलए वांतिवक ्र य भारत सरकार के ऽर्ये

ँऽशासिनक ँेणी के एक अधिकारी के िलए इस तरह के ्र य कऽ अधिकतम सीमा के अनुसार ढदया जाएगा।

12. कितपय मामल□ मऽ सदंय का बैठक मऽ भाग न लेना.- कोई सदंय, िजसका ँऽाधिकरण या इसकऽ सिमितय□ कऽ ढकसी

बैठक मऽ िवचार मऽ लाए गए ढकसी मामले मऽ ँऽऽयैता या अँऽऽयैता आऽथक िहत है, सुसंगत

पऽरिंथितय□ का उसे पता चलने के

बाद ऐसी बैठक□ मऽ उसके िहत के ँऽकार का यथाशीऽ/ ँऽकटीकरण करेगा और ऐसा ँऽकटीकरण

ँऽाधिकरण और इसकऽ

सिमितय□ कऽ कारऽणवाऽिहय□ के िलए अभिलिखत ढकया जाएगा तथा वह सदंय ँऽाधिकरण और इसकऽ सिमितय□ के इस

मामले के संबंध मऽ ढकसी भी िवचार िवमशऽण और िनणऽणय मऽ भाग नहऽ लेगा।

13. ढरि□यां आऽद, ँऽाधिकरण कऽ कायऽणवाही अिविधमाऽय न होना.- ँऽाधिकरण और इसकऽ सिमितय□

का कोई भी कायऽण या

कायऽणवाही केवल इस कारण से अमाऽय नहऽ कऽ जाएगी ढक:-

(क) ंाधिकरण और इसकऱ सिमितय के ढकसी ढरि या गठन मऱ कोई ँुट है;

(ख) ंाधिकरण और इसकऱ सिमितय के ढकसी सदंय के ँप मऱ कायऱरत ढकसी ँ ि कऱ

िनयुि मऱ कोई ँुट है;

(ग) ंाधिकरण और इसकऱ सिमितय कऱ ंऱढया मऱ कोई अनियमितता जो मामले के गुणदोष को

ंभावित नहऱ करती

है;

14. सदभावपूवऱरत कऱ गई कारऱरवाई के िलए संरंण.- सदभावना मऱ ढकए गए या इन िनयम के अधीन

ढकए जाने वाले कायऱरत

के िलए केऱंीय सरकार या ंाधिकरण या केऱंीय सरकार के ढकसी अधिकारी या ंाधिकरण के

ढकसी सदंय या अधिकारी

या अऱय कमऱरतारी के िवऱ कोई वाद अभयुग या अऱय िविधक कायऱरत नहऱ कऱ जाएगी।

¹Hkkx IIµ[k.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

5

अनुसूची 1

ढ. सं.	पदनाम	वेतनमान	पद कऱ सं या
1.	महांबंधक	पी.बी.-4+ जीपी #. 8700	01
2.	सहायकमहांबंधक	पी.बी.-3+ जीपी #. 5400	01
3.	ऱर्येलेखा अधिकारी	पी.बी.-3+ जीपी #. 5400	01
4.	सहायकलेखा अधिकारी	पी.बी.-2+ जीपी #. 4800	02

अनुसूची 2

ंाधिकरण के कायऱरत मक अनुभाग

(1) ंशासन:

(i) िनिध के उंेय को पूरा करने के िलए, आवं यक या ठीक समझे जाने वाले सभी ंशासिनक

काय कऱ ँ थापना,

सुसित करना, अनुरंण और ंशासिनक पढरचालन करना

(ii) ंाधिकरण और ंाधिकरण संबंधी मामल कऱ सिमितयां।

(2) निवेश/निध ंबंधन:

- (i) जमा राशि का अनुरोध, ढकसी रां्रीयकृत ब.क के ढ याजधारी खाते मः इसका निवेश करना।
- (ii) ंाधिकरण का जमा खाता खोलना और िविनधानकताऒन के खाता ं याभूितय को इसमः ं थानांतरत करना और दावे के िनपटारे के पं चात ंतिभूितय को िविनधानकताऒन खाते मः अंतरत करना।

(3) दावा और िनपटान:

- (i) अधिनयम कऒ धारा 125 कऒ उपधारा (3) के खंड (क) के और उसके अंतगऒत बनाए गए िनयम के अनुसार िविनधानकताऒन ंद्वारा दऒऒ कराए गए दाव के संबंध मः पां िविनधानकताऒन को सही ंदऒया पालन करने के पं चात ंतिदाय करना।
- (ii) अदालत या ंाधिकरण के आदेशानुसार गबन कऒ ंई राशि का िवतरण।
- (iii) िविधक और ंवतऒन िवभाग के साथ परामशऒन करके वापस कऒ ंई राशि का िवतरण
अधिकरण या ंाधिकरण,
यथांथित के आदेशानुसार ढकसी ऐसे पां और पहचाने गए ंतिभूितधारी को करना िजसने ढकसी ः यि त के गलत काय के सऒयक से नुकसान कऒ हो। िवतरत कऒ जाने वाली राशि ढकसी िवशेष आदेश संबंधी वापस कऒ ंई राशि तक सीमित होनी चाहिए और िवतरण के िलए ढकसी अऒ य राशि का उपयोग नहऒ ढकया जा सकता है।

(4) िविध और ंवतऒन:

- (i) अनुपालन नहऒ करने वाली कंपिनय/ः यि तय के िवऒ िविधक मामल कऒ शुआत।
- (ii) दावा या िनपटान अथवा अऒ य ढकसी िववाद से उऒु िविधक मामल और िववाद पर कायऒवाही करना।
- (iii) अधिनयम कऒ धारा 37 और धारा 245 के अधीन सदं य, िडवऒचरधाऒरय या िनऒेपकताऒन ंद्वारा ढकए गए

००णी काय॒भ्रवा॒द को जा॒री रखने म॒थ आ॒ए वि॒विध क ू य को पू॒रा करने के िल॒ए िनि॒ध से रा॒शि का ॒रुति॒पू॒त कर॒ना जैसा ॒क अध॒करण ॒द्वारा ॒इस सं॒बंध म॒थ वि॒वि॒ह॒त ॒रु॒द॒या के अ॒नु॒सार वि॒वि॒ह॒त है।

(5) वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र शि॒र्ा और सं॒र॒ण:

(i) वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र शि॒र्ा और सं॒र॒ण काय॒भ्र क॒लाप ॒ म॒थ लगे ॒थे सं॒ग॒ठन ॒ या सं॒ं था॒न ॒ या ३ याव॒सा॒यिक ि॒न॒काय ॒ या उ॒ोग और वा॒णि॒य मंड॒ल या अ॒य सं॒ग॒ठन ॒ को रि॒जं॒दीकृत ॒कर॒ना।

(ii) का॒रपो॒रेट सु॒शा॒सन, अ॒नु॒सं॒धा॒न काय॒भ्र सि॒हत वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र शि॒र्ा और सं॒र॒ण के ॒े॒ म॒थ सं॒गो॒ठी, काय॒भ्र॒म, प॒द॒र॒यो॒ज॒ना या काय॒भ्र क॒लाप ॒ के िल॒ए पं॒जीकृत ि॒न॒काय ॒ को अ॒नु॒दा॒न क॒ सं॒ वी॒कृ॒ति दे॒ना।

(iii) अ॒नु॒दा॒न क॒ सं॒ वी॒कृ॒ति के उ॒े॒ य ॒ क॒ पू॒त को सु॒नि॒त च॒त करने के िल॒ए अ॒नु॒दा॒न के ॒योग पर ि॒न॒ग॒रा॒नी रख॒ना। (iv) वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र शि॒र्ा, का॒रपो॒रेट सु॒शा॒सन, जा॒ग॒र॒क॒ता और सं॒र॒ण काय॒ ॒ म॒थ सं॒ल ॒ सं॒ं था॒न ॒ का सा॒थ और/या स॒ह॒यो॒ग दे॒ना।

(v) अ॒प॒ने वां॒ते या वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र शि॒र्ा और सं॒र॒ण म॒थ लगी इ॒का॒इय ॒ या शै॒र्िक सं॒ं था॒न ॒ या अ॒य ि॒न॒या॒मक इ॒का॒इय ॒ जैसे शे॒यर बा॒जार, डि॒पो॒से॒टरी, ब॒क और पा॒रं॒प॒द॒रक ि॒नि॒धय ॒ के स॒ह॒यो॒ग से सं॒गो॒ठी और वि॒चा॒र गो॒ठी सि॒हत रा॒ ॒ यापी वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र शि॒र्ा और जा॒ग॒र॒क॒ता प॒द॒र॒यो॒ज॒ना का आ॒यो॒ज॒न कर॒ना।

(vi) अ॒नु॒सं॒धा॒न और ॒रि॒श॒ण ॒द॒याक॒लाप ॒ सि॒हत काय॒भ्र॒म; प॒द॒र॒यो॒ज॒ना और काय॒भ्र॒यो॒ज॒ना के िल॒ए इ॒सके ल॑ य और ३ यय को ११ या॒न म॒थ रख॒ते ॒थे सं॒ं था॒गत ३ यव॑ं था या अ॒व॒सं॒र॒च॒ना क॒ सं॒ं था॒प॒ना कर॒ना।

(vii) वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र के ि॒हत उ॒े॒ य और ि॒नि॒ध को ॒ा॒त करने के िल॒ए सू॒च॒ना ॒ का ॒का॒शन और ॒चा॒र-॒सा॒र। (viii) वि॒वि॒न॒धा॒न॒क॒ता॒भ्र के ि॒हत सं॒बंधी मु॒ पर के॒य ॒ीय सर॒का॒र को स॒ला॒ह दे॒ना।

(ix) पूं॒जी बा॒जार के वि॒का॒स के िल॒ए वि॒शेष अ॒यय॒न/अ॒नु॒सं॒धा॒न/वि॒व॒ ले॒षण ॒यो॒जित ॒कर॒ना।

(6) वि॒व॒ त, ले॒खा और ला॒गत :

(i) निधय के अंतवाह और बिहवाह लेखा का अनुरोध करना।

(ii) विनिधानकता के खात का समवय करना।

(iii) सभी लेखा हरपोट, लेखा परीक्षा काय और वाष्क हरपोट क तैयारी करना।

(iv) के 3 ंतीय सरकार को हरटन फाइल करना।

(v) ंाधिकरण का बजट तैयार करना और इसक िनगरानी करना।

(vi) अपने-अपने लेखा मं विनिधानकता के दाव का खाता

लेखा करना। (vii) विनिधानकता क िनिधय और

ंतिभूितय के लेखा क ंदया।

(7) अध य, ंशासिनक अपेक्षा के अनुसार काय का पुनः आबंटन, विलयन या विभाजन का उप-विभाजन कर सकते ह।

[फा. सं. 05/27/2013-आईपीएफ]

मनोज कुमार, संयु सिचव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 13th January,
2016

G.S.R. 26(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (5), (6) and (7) of section 125 read with section 469 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

¹Hkkx Iµ[k.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

7

1. Short title, extent and commencement. - (1) These rules may be called the Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016.

2. Definitions.—(1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Companies Act, 2013;

(b) “Authority” means the Investor Education and Protection Fund Authority constituted under sub-section (5) of section 125 of the Act;

(c) “Chairperson” means the chairperson of the authority appointed under rule (5) of these rules;

(d) “Company” means company as defined in sub-section (20) of section 2 of the Act and includes ‘corresponding new bank’ as defined in sub-section (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970) and clause (b) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980);

(e) “Fund” means the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established under section 125 of the Act;

(f) “Investor” means any person, who has committed money in shares, or debentures, bond or deposits under a scheme or plan of a company registered under the Act;

(g) “Member” means members of the Authority appointed under sub-section (6) of section 125 of the Act; and

(h) “Section” means the section of the Act.

(2) Words and expressions used in these rules and not defined herein but defined in the Act or in the Companies (Specification of Definitions Details) Rules, 2014, shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act or in the said rules.

3.Establishment of the Authority.- The Authority shall be established on such date as may be notified by the Central Government.

4. Composition of the Authority.- (1) The Authority shall consist of the following, namely:-

- (a) Chairperson
- (b) six members
- (c) Chief Executive Officer

(2) The Chief Executive Officer shall be the convenor of the Authority.

5. Chairperson of the Authority.- The Secretary, Ministry of Corporate Affairs shall be the *ex-officio* Chairperson of the Authority.

6. Chief Executive Officer of the Authority.- The Central Government shall appoint a person to be the Chief Executive Officer of the Authority.

7. Members of the Authority.- The Central Government may appoint the following as the members of the Authority, namely:—

- (i) a person not below the rank of Executive Director to be nominated by the Reserve Bank of India as *ex-officio* member;
- (ii) a person not below the rank of Executive Director to be nominated by the Securities and Exchange Board of India as *ex-officio* member;
- (iii) four persons having special knowledge and experience of not less than fifteen years, in finance, management, accountancy or law with one person from each discipline and such person shall have special knowledge, or professional experience, which shall in the opinion of the Central Government shall be useful to the Authority.

8.The term of office of members of the Authority.- (1) The members of the Authority appointed under clause (iii) of rule 7 shall hold office for a period of three years and shall be eligible for reappointment;

Provided that no member shall hold office for more than three terms.

Provided further that a member shall be eligible for reappointment after expiration of cooling off period of three years after his term.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Central Government shall have the right to terminate the services of a member appointed under clause (iii) of rule 7, at any time before the expiry of the period specified under sub-rule (1), by giving him notice of not less than three months in writing for reasons mentioned in sub-rule (4), and a member shall also have the right to relinquish his office, at any time before the expiry of the period specified under sub-rule (1), by giving to the Central Government notice of not less than three months in writing.

(3) The members appointed under clause (iii) of rule 7 shall hold office for a period of three years or till attaining the age of 65 years whichever is earlier.

(4) The Central Government shall remove a member from office if he—

- (a) is, or at any time has been, adjudicated as insolvent;
- (b) is of unsound mind and stands so declared by a competent court;
- (c) has been convicted of an offence which, in the opinion of the Central Government, involves a moral turpitude;
- (d) has, in the opinion of the Central Government, so abused his position as to render his continuation in office detrimental to the public interest.

Provided that no member shall be removed under this sub-rule unless he has been given a reasonable opportunity of being heard in the matter.

9. The number of officers and employees of the Authority.- The Authority shall have such number of officers and other employees for rendering secretarial assistance and for its day to day functions as are set out in Schedule I to these rules.

10. Functions of the Authority.- (1) Subject to the provision of the Act, the Authority shall have the duty to administer the Fund for Investor Education and Protection.

(2) The general management of the affairs of the Authority shall vest in the Chief Executive Officer, who may exercise powers, which may be authorised by the Authority.

(3) The Chief Executive Officer shall function under superintendence and direction of the Chairperson.

(4) Without prejudice to the generality of the provisions, the functions of the Authority shall include the following, namely:-

(a) The Authority may constitute permanent Committees for overseeing its functions;

(b) Each Committee shall comprise two members, Chief Executive Officer and concerned functional head, who shall be the secretary of the Committee. The Committee shall be headed by an ex-officio member;

(c) The Committee may invite experts with special knowledge and expertise, as and when required to assist it on any specific issue;

¹Hkkx Ilμ[k.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

9

(b)The Authority may outsource, if required, work related to Funds and Shares Management.

(c) The broad functional divisions of the Authority shall be as per Schedule II to these rules.

11. Meetings.- (1) The Authority and its Committees shall meet at such times and places as it may consider necessary.

(2)The Authority and its Committees shall determine its own procedure for holding of meetings.

(3) If the Authority or its Committees has to hold a meeting elsewhere than in New Delhi, the approval of the Chairperson of the Authority shall be obtained indicating the reasons thereof. (4) The Authority and the Committees shall meet at least once in a quarter and at least four such meetings shall be held in a financial year:

Provided that not more than one hundred and twenty days shall intervene between two consecutive meetings.

(5) The meeting of the Authority shall be presided over by the Chairperson.

(6) If for any reason, the Chairperson is unable to attend a meeting, any other Member chosen by the Members present from amongst themselves at the meeting shall preside over the meeting.

(7) In case of difference in opinion on any question before the Authority, or any of its Committees, the views of the majority shall be taken as the final decision.

(8) More than fifty percent appointed Members of the Authority shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Authority.

(9) Two members of a Committee shall constitute the quorum for the transaction of business at a meeting of the Committee.

(10) For journeys performed by a non-official member of the Authority or Committee or a special invitee in connection with the work of the Authority or Committee, the actual expenditure for attending the meeting shall be reimbursed, subject to maximum of such expenditure limit applicable to a Senior Administrative Grade officer of Government of India.

12. Member not to participate in meetings in certain cases.- A member, who has any pecuniary interest, direct or indirect in any matter that is brought up for consideration at a meeting of the Authority and its Committees, shall, as soon as possible after relevant circumstances have come to his knowledge, disclose the nature of his interest at such meeting and such disclosure shall be recorded in the proceedings of the Authority and its Committees, and the member shall not take

any part in any deliberation or decision of the Authority and its Committees with respect to that matter.

13. Vacancies, etc., not to invalidate proceedings of Authority.- No act or proceeding of the Authority and its Committees shall be invalid merely by reason of-

- (a) any vacancy in, or any defect in the constitution of the Authority and its Committees;
- (b) any defect in the appointment of a person acting as a member of the Authority and its Committees;
- (c) any laches in the procedure of the Authority and its Committees not affecting the merits of the case.

14. Protection of action taken in good faith.- No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Central Government or Authority or any officer of the Central Government or any member, officer or other employee of the Authority for anything, which is in good faith done or intended to be done under these rules.

Schedule I

S. No.	Designation	Pay Scale	Number of posts
1.	General Manager	PB-4 + GP Rs. 8700	01
2.	Assistant General Manager	PB-3 + GP Rs. 5400	01
3.	Senior Accounts Officer	PB-3 + GP Rs. 5400	01
4.	Assistant Accounts Officer	PB-2 + GP Rs. 4800	02

Schedule II

Functional Divisions of the Authority

(1) Administration:

- (i) Establishing, equipping, maintaining and operating administrative functions as may be necessary or deemed expedient for fulfilling the objects of the Fund.
- (ii) Authority and committees of Authority related matters.

(2) Investment/ Funds Management:

- (i) Maintaining funds standing to the credit of Fund, investing the same in interest bearing account of any nationalised bank.
- (ii) Opening of depository account of authority and transferring into the account securities of investor and transferring to investors account securities upon settlement of the claim.

(3) Claims and Settlement:

- (i) Making refunds to eligible investors after following due procedure in respect of claims lodged by investors in accordance with clause (a) of sub-section (3) of section 125 of the Act and rules made thereunder.
- (ii) Distribution of disgorged amount as per the order of the court or the Authority.
- (iii) Distribution of disgorged amount in consultation with Legal and Enforcement Division, to eligible and identified security holders who have suffered losses due to any wrong actions of any person in accordance with the order of Tribunal or order of the Authority, as the case may be. The amount to be distributed shall be limited to amount disgorged in respect of any particular order and no other funds can be used for distribution.

(4) Legal and Enforcement:

- (i) Initiation of legal cases against non-compliant companies or persons.
- (ii) Handling disputes and legal cases arising out of claims or settlement or any other dispute.

- (iii) Reimbursement of funds from Fund for meeting legal expenses incurred in pursuing class action suits under section 37 and 245 of the Act by members, debenture holders or depositors as sanctioned by Tribunal in accordance with the procedure prescribed in this regard.

(5) Investor Education and Protection:

- (i) Registering associations or institutions or professional bodies or chambers of commerce and industry or other organisations engaged in investor education and protection activities.
- (ii) Sanctioning grants to the registered entities for seminars, programmes, projects or activities in the field of corporate governance, Investors' Education and Protection including research activities.
- (iii) Monitoring of the utilisation of the grants to ensure the achievements of the objectives of the sanctioning of the grants.
- (iv) Cooperating and collaborating with institutions engaged in Investor Education, corporate governance, awareness, and protection activities.

¹Hkkx Πμ[k.M 3(i)^o

Hkkjr dk jkti=k % vlk/kj.k

11

- (v) Conducting on its own or in collaboration with entities engaged in Investor education and protection or academic institutions or other regulated entities like Stock Exchanges, Depositories, Banks and Mutual funds nationwide investors' education and awareness programmes including seminars and symposia.
- (vi) Setting up of institutional arrangements or infrastructure for taking up programmes; projects and action plans keeping in view the objectives and expenditure relating thereto, including research and training activities.
- (vii) Publishing and disseminating information for investors' benefit and objects and achievements of the Fund.
- (viii) Advising Central Government on the issues related to Investors' interest.
- (ix) Sponsor specific studies or research or analysis for the development of capital market.

(6) Finance, Accounts and Audit:

- (i) Maintenance of accounts of inflow and outflow of funds.
- (ii) Reconciliation of accounts of investors.
- (iii) Preparation of all accounting reports, audit work and annual report.
- (iv) Returns to Central Government.
- (v) Preparation of budget of authority and its monitoring.
- (vi) Accounting for all claims of investor in respective accounts.
- (vii) Procedure for accounting of investors' funds and securities.

(7) The Chairperson may re-allocate functions, merge or sub-divide divisions as per administrative requirement.

[F. No. 05/27/2013-IEPF]

MANOJ KUMAR, Jt. Secy.